

राज्यपाल ने सगिरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (वजिजापन का प्रतषिध और व्यापार तथा वाणजिय, प्रदाय और वतिरण का वनियिमन) (छत्तीसगढ संशोधन) वधियक पर कयि हस्ताक्षर

चरचा में क्यो?

19 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सगिरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (वजिजापन का प्रतषिध और व्यापार तथा वाणजिय, प्रदाय और वतिरण का वनियिमन) अधनियिम, 2003 में संशोधन हेतु प्रस्तुत वधियक पर हस्ताक्षर कयि हैं। अब इस वधियक को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजा जाएगा।

प्रमुख बदि

- इस अधनियिम की धारा 3, 4, 12, 13, 21 एवं 27 में संशोधन कयि गया है। इसके अनुसार धारा 4 में संशोधन कर धारा 4-क और 4-ख जोड़ी गई है।
- धारा 4-क के अनुसार 'हुक्का बार पर रोक- इस अधनियिम में अन्तर्वषिट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, स्वयं या किसी अन्य व्यक्तिकी ओर से, कोई हुक्का बार नहीं खोलेगा या हुक्का बार नहीं चलाएगा या भोजनालय सहति किसी भी स्थान पर ग्राहकों को हुक्का नहीं देगा।'
- धारा 4-ख के अनुसार 'हुक्का बार में हुक्के के माध्यम से धूम्रपान पर रोक- कोई भी व्यक्ति, किसी भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का या नरगलि (गड़गड़ा) के माध्यम से धूम्रपान नहीं करेगा।'
- धारा 13 में संशोधन कर नवीन धारा 13-क जोड़ी गई है। धारा 13-क के अनुसार 'हुक्का बार के मामले में ज़ब्त करने की शक्ति- यदि कोई पुलिसि अधिकारी/आबकारी अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हो, और जो उप-नरीक्षक की श्रेणी से नमिन का न हो, के पास यह वशिवास करने का कारण है कि धारा 4-क के प्रावधानों का उल्लंघन कयि गया है या उनका उल्लंघन कयि जा रहा है, वह हुक्का बार के वषिय या साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली किसी भी सामगरी या वस्तु को ज़ब्त कर सकेगा।'
- मूल अधनियिम की धारा 21 में संशोधन करते हुए नवीन धारा 21-क एवं 21-ख जोड़ी गई है। धारा 21-क के अनुसार 'हुक्का बार चलाने के लयि दंड- जो कोई, धारा 4-क के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह ऐसे कारावास, जो कतिन वर्ष तक का हो सकेगा, कति जो एक वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना, जो कतिचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, कति जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगा, से दंडनीय होगा।'
- इसी प्रकार 21-ख के अनुसार हुक्का बार में हुक्का के माध्यम से धूम्रपान के लयि दंड- जो कोई, धारा 4-ख के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे ऐसे जुर्माने, जो कतिचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, कति जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगा, से दंडति कयि जाएगा।'
- धारा 27 में संशोधन करते हुए नवीन धारा 27-क जोड़ी गई है। धारा 27-क के अनुसार 'धारा 4-क के तहत अपराध का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना- इस अधनियिम में अन्तर्वषिट किसी बात के होते हुए भी, धारा 4-क के तहत कारति अपराध, संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।'